



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4

दिनांक: 07.12.2020

विषय :- राज्य सरकार के इच्छुक मंत्रालयों/विभागों में आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुस्मरण-प्रथम

समस्त मुख्य अभियन्ता (परि०एवंअनु०/परी०एवंपरि०/एम०एम०/क्रय एवं अनु०)

महाप्रबन्धक (वित्त)/ (विधि),

समस्त अधीक्षण अभियन्ता (परि०एवंअनु०/परी०एवंपरि०/एम०एम०/क्रय एवं अनु०/कारपोरेट प्लानिंग)

उपमहाप्रबन्धक (मु०भु०इ०)

समस्त अधिशासी अभियन्ता (परि०एवंअनु०/परी०एवंपरि०/एम०एम०/क्रय एवं अनु०)

पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 1862/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4 दिनांक 01.12.2020 के द्वारा उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1296/1(2)/2020/05-01/2020T.C. दिनांक 06.11.2020 की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित कर पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी योजनाओं, जिनमें आधार का प्रयोग किया जाता है, हेतु Meity, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आधार अधिप्रमाणन को प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 06.12.2020 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु आतिथि तक भी आपके द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय का उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना दिनांक 10.12.2020 तक अवश्यमेव इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे तदनुसार प्रस्ताव/आख्या उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जा सके।

सलग्नक:-यथोपरि।

(पी०सी० ध्यानी)
निदेशक (मा०सं०)

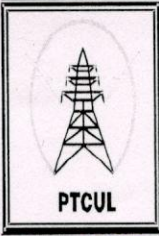
पत्रांक: 1913 /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (परिचालन)/ (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नक:-यथोपरि।

(पी०सी० ध्यानी)
निदेशक (मा०सं०)



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 1862/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4

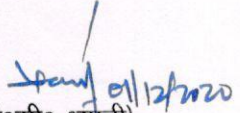
दिनांक: 01.12.2020

विषय :- राज्य सरकार के इच्छुक मंत्रालयों/विभागों में आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1296/1(2)/2020/05-01/2020T.C. दिनांक 06.11.2020 की छायाप्रति संलग्नकों सहित आपको इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी योजनाओं, जिनमें आधार का प्रयोग किया जाता है, हेतु MeitY, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आधार अधिप्रमाणन को प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 06.12.2020 तक इस कार्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें, जिससे तदनुसार प्रस्ताव/आख्या उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक:-यथोपरि।



(पी०सी० ध्यानी)
निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक: /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (परिचालन)/परियोजना/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।


(पी०सी० ध्यानी)
निदेशक (मा०सं०)

2406 No.IMD/PTCUL/... Dt. 23/11/2020

DIR(HA)

प्रेषक,

जे०पी० मैखुरी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीसीएल/पिटकुल/यूजेवीएनएल लि०,
देहरादून।

प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून:दिनांक 06 अक्टूबर, 2020

विषय-राज्य सरकार के इच्छुक मंत्रालयों/विभागों में आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के क्रम में सचिव सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-FileNO. IT-MISC/GOI/1/2020-XXXIV-1-Information Technoigy दिनांक-रहित, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रश्नगत प्रकरण पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुये प्रस्ताव/आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(जे०पी० मैखुरी)
अनु सचिव।

✓ हस्तापूर्णा/समयबद्ध
✓ अग्रप्रबन्धक (मा०सं०)
✓ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
श्री कमल/सह सचिव ज.अधी-1
श्रीमती दीपा सचिव सहायता/
श्री विपिन/सह सचिव सहायता.-1
श्रीमती रोमा, सचिव सहायता.-III
कैम्प कार्यालय (मा०सं०)
कृपया दि० 27/11/2020 को 11:30 बजे
वर्षा करें।
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

कार्यालय निदेशक (मा०सं०)
पत्र प्रेषित की दिनांक 25-11-2020 समय 1:25 pm
जायरी संख्या 1879

प्राप्तकर्ता

निदेशक (मा०सं०) 25/11/2020

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 2630
File
Date 25-11-20

SPD
25/11

I/1939/2020

उत्तराखण्ड शासन
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-1
देहरादून दिनांक: सितम्बर, 2020

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Asst. Secy/IT
4/104/Secy/IT/20
5/10/20

कृपया MeitY, भारत सरकार के पत्र दिनांक-18.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 को दिनांक-05.08.2020 को MeitY, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा राज्य सरकार के इच्छुक मंत्रालयों/विभागों में आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग किये जाने हेतु इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर संलग्न प्रार्थना पत्र के प्रारूप को भरकर केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग किये जाने के प्रस्ताव को तैयार किये जाने हेतु दिशानिर्देश भी संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं।

कृपया अपने-अपने विभागान्तर्गत चल रही ऐसी योजनाओं, जिनमें आधार का प्रयोग किया जाता है, हेतु MeitY, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आधार अधिप्रमाणन को प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by RAMESH
KUMAR SUDHANSHU
Date:Thu Oct 01 11:44:58 IST
2020
Reason: Approved

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक-उक्तवत्।

1. प्रतिलिपि निदेशक आई0टीडी0ए0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. गार्ड फाइल।

1. 581/AS/IT/2020

D.S.(E)

08/10/2020

आज्ञा से

(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।

13/11/20

संख्या 739/2018-EG-II (Vol-II) भारत सरकार
 Government of India
 दिनांक 21/08/2020 मुख्य सचिव/20.20

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 Ministry of Electronics & Information Technology
 इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
 Electronics Niketan, 6, C G O Complex, New Delhi-110003
 Website: www.meity.gov.in

संख्या 13(6)/2018-EG-II(Vol-II)
 No.....

दिनांक 18.08.2020
 Date.....

CIRCULAR

Subject: Application Form along with Guidelines for submission of proposals for use of Aadhaar authentication under the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020-regarding

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has notified the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 in the Gazette of India on 05.08.2020 (copy enclosed).

2. As per Rule 4 of aforesaid notification, the Ministry or the Department of the Government of India or the State Government, as the case may be, desirous of utilising Aadhaar authentication for a purpose specified in rule 3 shall prepare a proposal with justification in regard to such purpose for which Aadhaar authentication is sought and submit the same to the Central Government for making a reference to the Authority.

3. In this regard, an Application Form (Annexure-I) along with Guidelines (Annexure-II), for submission of proposals for use of Aadhaar authentication under above rules, is enclosed herewith for reference.

This has the approval of competent authority.

Handwritten notes in Hindi: "इस पर सब अफसरों की इंटर प्रसंशर की" and "Amralkash 21.08.20".

Handwritten signature: "AS (IEST) 21/08/20".

Archana Dureja
 Scientist 'G'/Sr. Director
 Tel. no. 24362528

To: Secretaries of all Ministries/ Departments of Govt. of India
 Chief Secretaries of all States/ UTs

Handwritten: "363 To: IIA S.O. (IT) 24/08/2020"

Handwritten: "मौखिक 10/08/20, 1002/202, दिनांक 24/8/2020"



Handwritten: "श्री मनीष, RO 24-08-2020" and "स्वच्छ भारत" logo.



**APPLICATION TO MEITY FOR ALLOWING USE OF AADHAAR
AUTHENTICATION**

{under Rule 4 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare,
Innovation, Knowledge) Rules, 2020}

To,

The Secretary,
The Ministry of Electronics and IT,
Government of India,
Electronics Niketan,
6, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003.

Sir/Madam,

The (Name of Ministry/Department of Central or State government) would like to use Aadhaar authentication services for(use-case) as per the provisions of Section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. This application is being made under Rule 4 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 for approval of the purpose of use of Aadhaar to the Central Government.

The details of the use-case, applicable purpose, justification and proposed Authentication User Agency/KYC User Agency are provided in the prescribed format at Annexure I. Any other information/ document will be provided immediately to the Ministry or UIDAI, as and when required.

(Signed by)
Secretary of the Ministry/Head of Department

Annexure I

(Please refer to guidelines in Annexure II for preparing the proposal and application form).

Applicant Ministry/Department Details						
1.	Name of Applicant Ministry/Department					
2.	Registered office address					
3.	Correspondence address					
Contact Details						
4.	Contact Name					
5.	Designation					
6.	Email Address					
7.	Mobile Number					
8.	Office Number					
9.	Brief Description of initiative / scheme (Ecosystem and processes involved in achievement or delivery of benefit)					
Authentication Requirements						
10.	Proposed Aadhaar authentication service Use case					
11.	Aadhaar Authentication service Use case will meet following Purpose- (a) usage of digital platforms to ensure good governance; (b) prevention of dissipation of social welfare benefits; and (c) enablement of innovation and the spread of knowledge. {Ref: Rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020}					
12.	Justification for the Use-case to be considered for the above purpose					
13.	Name of proposed Authentication User Agency (AUA) / e-KYC User Agency (KUA) for the use of Aadhaar Authentication services					
14.	Aadhaar Authentication services proposed to be used(Please select one)	<table border="1"> <tr> <td>Yes/No Authentication</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yes/No and eKYC</td> <td></td> </tr> </table>	Yes/No Authentication		Yes/No and eKYC	
Yes/No Authentication						
Yes/No and eKYC						
Other details (May be attached separately)						
15.	Technology Architecture of the authentication system to be deployed	Attached (Yes/No)				
16.	Service delivery process using Aadhaar authentication and eKYC	Attached (Yes/No)				
17.	In principal commitment of the Ministry/Department to comply with all security and privacy provisions of the Aadhaar Act, 2016, regulations thereunder and various guidelines issued by UIDAI	(Yes/No)				

(Signed by)
Secretary of the Ministry/Head of Department

Annexure-II

Guidelines for Central / State Government Ministries / Departments to submit proposals to the Central Government for Aadhaar authentication under the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020.

The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Aadhaar Act) was amended in 2019 following Supreme Court's judgment dated 26.09.2018 in Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012 [Justice K S Puttaswamy (retd) & anr vs Union of India vs ors]. The amendments include addition of sub-section (4) in Section 4 of the Aadhaar Act reproduced below:

"(4) An entity may be allowed to perform authentication, if the Authority is satisfied that the requesting entity is –

- (a) compliant with such standards of privacy and security as may be specified by regulations; and*
- (b) (i) permitted to offer authentication services under the provisions of any other law made by Parliament; or*
 - (ii) seeking authentication for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State, may prescribe."*

2. Further, clause (aa) was added in sub-section (2) of section 53 enabling the Central Government to make rules for *"the purpose for which the requesting entity may be allowed by the Authority to perform authentication under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4"*.

3. Accordingly, the Central Government has notified the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (the Rules) published in the official gazette on 05.08.2020 (Annexe) permitting Aadhaar authentication on voluntary basis for following purposes (Rule 3):

- (i) usage of digital platforms to ensure good governance;
- (ii) prevention of dissipation of social welfare benefits; and
- (iii) enablement of innovation and spread of knowledge.

4. Proposals for Aadhaar authentication can be prepared for consideration of the Central Government by a Department or Ministry of Government of India or a State Government. The proposal may be prepared keeping in view the following aspects:

- (i) Proposals which would be eligible for consideration under section 7 (i.e. involving giving of subsidy, benefit or service for which expenditure is incurred from

Consolidated Fund of India or Consolidated Fund of State) may be made under the provisions of that section only and in accordance with UIDAI's Circular No. 1-1/2019-UIDAI(DBT) dated 25.11.2019.

- (ii) Proposals which do not qualify for consideration under section 7, but fulfil one or more of the purposes may be preferred under the Rules.
- (iii) The proposal should contain a brief description of the initiative or scheme highlighting the benefit that would accrue from its implementation. Such benefit should be relatable to the purpose(s) specified under Rule 3, for example, by facilitating participation, accountability, transparency, responsiveness, efficiency, effectiveness, equity, inclusion etc. which reduce or eliminate transaction costs, or promote ease of living of residents or enable better access to services for them. The justification in regard to the purpose(s) under Rule 3 should be brought out clearly.
- (iv) The proposal should briefly explain the eco-system and the processes involved in achievement or delivery of the benefit.
- (v) It should specify the type of Aadhaar authentication service proposed to be used (whether yes/no authentication or yes/no and e-KYC authentication).
- (vi) The name of Authentication User Agency (AUA)/e-KYC User Agency (KUA) proposed for the use of Aadhaar authentication services should be mentioned.
- (vii) Technology architecture of the authentication system to be deployed should be highlighted.
- (ix) The service delivery process using yes/no authentication and eKYC should be described.
- (x) In principal commitment of the sponsoring Ministry/Department or State Government to comply with all security and privacy provisions of the Aadhaar Act, 2016, regulations thereunder and guidelines issued by UIDAI from time to time should be clearly indicated in the proposal.
- (xi) The proposal should be sent with the approval of the Secretary of the Ministry/Department in the Central Government, or the State Government, as the case maybe, to the Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110 003.
- (xii) The contact details of the officer incharge of the proposal (name, designation, address, email, mobile number) should be indicated.


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220856
CG-DL-E-05082020-220856

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]
No. 385]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

सा.का.नि.490(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18वां) की धारा 53 की उप-धारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 53 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत्त होना.— (1) ये नियम सुशासन के लिए आधार अधिग्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.— इन नियमों में संदर्भ के अनुसार जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) है;

(ख) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किये गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) में उनके लिए निर्धारित किया गया अर्थ ही होगा।

3. आधार अधिप्रमाणन के प्रयोजन- (1) केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच समर्थ करने लिए, अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दे सकती है, अर्थात्:-

(क) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग;

(ख) सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय की रोकथाम; तथा

(ग) नवोद्भव को समर्थ बनाना और ज्ञान का प्रसार करना।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा।

4. प्रस्ताव तैयार करना.- नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रस्ताव के बारे में औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार करेगा जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की गई है और इसे प्राधिकरण के संदर्भ के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

5. प्रस्ताव की जांच.- नियम 4 के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रस्ताव नियम 3 में वर्णित प्रयोजनों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है, तो यह केंद्र सरकार को सूचित करेगा कि अनुरोधकर्ता निकाय को आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाए और इसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, को केंद्र सरकार द्वारा इसे तदनुसार अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

[फा.सं. 13(6)/2018-ईजी-II (वॉल्यूम- II)]

डॉ. राजेंद्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

G.S.R.490(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 read with clause (aa) of sub-section (2) of section 53 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government, in consultation with Unique Identification Authority of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

(b) "Authority" means the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Act;

(c) Words and expressions used and not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them in the Act or in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

34. (40 I T)

50 f I T

50-1000

3. **Purposes for Aadhaar authentication.**— (1) The Central Government may allow Aadhaar authentication by requesting entities in the interest of good governance, preventing leakage of public funds, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them, for the following purposes, namely:—

- (a) usage of digital platforms to ensure good governance;
- (b) prevention of dissipation of social welfare benefits; and
- (c) enablement of innovation and the spread of knowledge.

(2) Aadhaar authentication under sub-rule (1) shall be on a voluntary basis.

4. **Preparation of proposal.**— The Ministry or the Department of the Government of India or the State Government, as the case may be, desirous of utilising Aadhaar authentication for a purpose specified in rule 3 shall prepare a proposal with justification in regard to such purpose for which Aadhaar authentication is sought and submit the same to the Central Government for making a reference to the Authority.

5. **Examination of proposal.**— On receipt of the proposal under rule 4, if the Authority is satisfied that the proposal is in accordance with the purposes mentioned in rule 3 and the provisions of the Act, it shall inform the Central Government that the requesting entity may be allowed to perform Aadhaar authentication and thereafter, the Ministry or the Department of the Government of India or the State Government, as the case may be, may be authorised by the Central Government to notify the same accordingly.

[F.No. 13(6)/2018-EG-II(Vol-II)]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.

05-21/2020
mrc 21/2020